भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1639
सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

कैरियर विकास केन्द्र के रूप में रोजगार कार्यालय

1639. श्री रामचरण बोहराः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रोजगार कार्यालयों को कैरियर विकास केन्द्र बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार रोजगार मिलान, आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएस परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1 राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस)पोर्टल (www.ncs.gov.in)

2. रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संस्थानों के सहयोग से आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करना।

3. एनसीएस परियोजना में संबंधित राज्य पोर्टल के माध्यम से रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल के साथ आपस में जोड़ने की भी परिकल्पना की गई।

प्रस्तावों तथा योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

अनुबंध

"कैरियर विकास केन्द्र के रूप में रोजगार कार्यालय" पर पूछे गए श्री रामचरण बोहरा द्वारा लोक सभा के दिनांक 02-03-2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1639 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि (लाख में)
1	अरुणाचल प्रदेश	21.18
2	असम	652.52
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33.96
4	आंध्र प्रदेश	325.96
5	बिहार	721.79
6	छत्तीसगढ़	512.59
7	दमन और दीव	7.04
8	दिल्ली	52.12
9	गोवा	11.00
10	गुजरात	563.86
11	हरियाणा	315.45
12	हिमाचल प्रदेश	115.93
13	जम्मू और कश्मीर	364.47
14	लद्दाख	18.01
15	झारखंड	311.48
16	कर्नाटक	454.55
17	केरल	92.95
18	लक्षद्वीप	10.65
19	महाराष्ट्र	128.61
20	मेघालय	56.09
21	मध्य प्रदेश	933.36
22	मणिपुर	32.77
23	मिजोरम	48.70
24	नागालैंड	148.81
25	ओडिशा	506.73
26	पुडुचेरी	68.41
27	पंजाब	133.14
28	राजस्थान	503.82
29	सिक्किम	67.70
30	तेलंगाना	397.81
31	त्रिपुरा	118.47
32	तमिलनाडु	814.27
33	उत्तर प्रदेश	878.23
34	उत्तराखंड	187.80
35	पश्चिम बंगाल	384.02